जबरन बेदखली को रूकवाने विरोध अथवा न्याय पाने के लिए उठाये जा सकने वाले कदम

1. याचिका /जनहित वाद (पीआईएल) दायर करना

जनहित वाद (पीआईएल) एक ऐसी याचिका है जो समाज के किसी भी सदस्य द्वारा जनहित के किसी भी मामले के लिए, जनहित को हुए किसी भी नुकसान के लिए दायर की जा सकती है। जबरन बेदखली से संबंधित मामलाओं में कोई भी प्रभावित व्यक्ति किसी वकील के माध्यम से दिल्ली उच्च न्यायालय अथवा निचली अदालत में बेदखली से हुए नुकसान के लिए जनहित याचिका प्रस्तुत कर सकता है।

जनहित याचिका किसी भी पीडित व्यक्ति द्वारा मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर कानूनी समाधान पाने के लिए दायर की जा सकती है। भारत के संविधान के अनुसार यह याचिका अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में या अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है।

जनहित याचिका जनहित वाद दायर करने के लिए जरूरी कदम

1. अपना वाद दायर करने के लिए किसी जनहित मामलों से सम्बंधित वकील अथवा संगठन (जैसे ह्यूमन राइट्स ला नेटवर्क) से संपर्क करें।
2. जरूरी साक्ष्य एकत्रित करें, जैसे पात्रता का अनुबंध, आवासीय साक्ष्य, पहचान का साक्ष्य, बेदखली के फोटो, नोटिस तथा पुनर्वास नीति (यदि कोई हो) आदि।
3. अदालत जाने वाले सभी पीडित पक्षों के नाम व पते आदि की सूची तैयार करें।
4. सभी सरकारी एजेंसियों जहां से कोई भी राहत मिल सकती है, के नाम व पतों की सूची तैयार करें।
5. मानवाधिकारों के उल्लंघन को बढ़ाने वाले तथ्यों की सूची तैयार करें।
6. प्रभावित पक्ष किसी स्थल विशेष में जिस तारीख से रह रहे हैं, जब बेदखली की कार्यवाही हुई, जब उन्हें नोटिस दिया गया, इन सबकी सूची तैयार करें।

2. मानवाधिकारों के उल्लंघन एवं बेदखली के दस्तावेज

- अपने मोबाइल पफोन से ध्वस्तीकरण के फोटोग्राफ खींचें।
- अपने मोबाइल पफोन या कैमरे में ध्वस्तीकरण का वीडियो तैयार करें।
- तैयार दस्तावेजों को प्रमाण के रूप में अदालत में प्रयोग करें तथा मीडिया, सक्षम गैर सरकारी संस्थाओं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ के विशेष प्रतिवेदक को भेजें।

3. बेदखली व पुनर्वास से संबंधित सूचना के लिए

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अपील दायर करना

सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई), 2005 के अंतर्गत कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी सरकारी कार्यालय, विभाग या अधिकारी से सूचनाएं मांग सकता है। यह अधिनियम सभी नागरिकों को समय से सूचना उपलब्ध कराने का प्रावधान करता है। यह अधिनियम सूचना चाहने वाले नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है:-

- अनुमति योग्य सरकारी दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त करना।
- अनुमति योग्य सरकारी दस्तावेजों का निरीक्षण करना।
- अनुमति योग्य सरकारी कार्यों का निरीक्षण करना व नमूने प्राप्त करना।

सूचना का अधिकार अधिनियम, सार्वजनिक सूचनाएं चाहने के लिए निम्नलिखित उपाय सुझाता है:-

1. चाही गयी सूचना का स्पष्ट उल्लेख करते हुए एक प्रार्थना पत्र लिखें। यह पत्र हस्तलिखित या टाइप किया हुआ हो सकता है तथा ईमेल से भी भेजा सकता है। सूचना चाहने वाले को पत्र लिखने में परेशानी होने पर वह लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) अथवा सहायक लोक सूचना अधिकारी से मौखिक रूप से भी प्रार्थना कर सकता है। उक्त अधिकारी संबंधित व्यक्ति की प्रार्थना को लिखने के लिए बाध्य हैं। यह प्रार्थना अंग्रेजी, हिंदी या संबंधित क्षेत्र की कार्यालयी भाषा में की जा सकती है।
2. प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थना शुल्क के रूप में दस रुपये का भुगतान करें। यह शुल्क डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक अथवा भारतीय पोस्टल आर्डर के रूप में भेजा जा सकता है अथवा संबंधित विभागीय लेखाधिकारी को नकद भी दिया जा सकता है। सूचना चाहने वाले को आगे अन्य शुल्क, जो उसे लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) द्वारा दस्तावेज मुहैया कराने के एवज में निर्धारित किया गया हो, वह भी देना होगा।

3. इस तरह उक्त प्रार्थना पत्र संबंधित सार्वजनिक संस्थान के लोक सूचना अधिकारी अथवा सहायक लोक सूचना अधिकारी को प्रेषित करें।
4. चाही गयी सूचना 30 दिन के भीतर प्राप्त न होने पर, अथवा लोक सूचना अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट न होने की सिथति में आवेदक अपील दायर कर सकता है।
5. यह अपील किसी भी सादे कागज में मूल प्रार्थना पत्र की प्रति के साथ संबंधित विभाग के प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रस्तुत की जा सकती है।
6. यदि प्रथम अपीलीय अधिकारी से भी सूचनाएं प्राप्त नहीं होती हैं तो आप सूचना आयोग में दूसरी अपील दायर कर सकते हैं।

विस्तृत जानकारी के लिए इस वेबसाइट का अवलोकन करें:

ीजजचरूतजपणपदकपणहवअण्पद ंदक ीजजचरूबपबणहवअण्पद

सक्षम सरकारी अधिकारियों तथा विभागों से आप निम्नलिखित सूचना मांग सकते हैं:-

- ध्वस्तीकरण की सूचना
- ध्वस्तीकरण का कारण और ध्वस्तीकरण के आदेश की प्रतियां
- पुनर्वास स्थल तथा वैकल्पिक आवास की जानकारी
- पुनर्वास सम्बन्धी नीति

4. बेदखली असर आकलन

हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क (एचएलआरएन) ने वर्ष 2007 में 'बेदखली असर आकलन के रूप में एक साधन विकसित किया जो संयुक्त राष्ट्रसंघ के मूल दिशा-निर्देशों तथा सिद्धांतों पर आधारित है। विकास आधारित बेदखली एवं विस्थापन सम्बन्धी किसी भी परियोजना की स्वीकृति अथवा उसे अंतिम स्वरूप देने से पूर्व 'बेदखली असर आकलन का विचार किया जाना चाहिए। ऐसा किया जाना संयुक्त राष्ट्रसंघ के मूल सिद्धांतों एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप आवश्यक है। इस नये साधन को बेदखली की कार्यवाही को रोकने में एक मशीनी तकनीक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है और जहां पहले ही बेदखली हो चुकी हो वहां यह सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है कि

न्यायसंगत व समुचित भरपाई, पुनस्थापन और मुआवजे का निर्धारण किया जाए। विकसित की गयी यह तकनीक जबरन बेदखली के दौरान हुए संपत्ति के नुकसान (जैसे भूमि, भवन, घरेलू सामान आदि) तथा गैर संपत्ति के नुकसान (जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि) का मूल्य निर्धारण पर केन्द्रित है। यह नयी तकनीक स्थानीय परिस्थितियों में अपनायी जा सकती है तथा व्यक्तियों, परिवारों, समुदायों एवं समाज पर बेदखली के वास्तविक प्रभावों का निर्धारण करने में भी प्रयोग में लायी जा सकती है। इस तकनीक के जरिए प्राप्त तथ्यों को सरकार के साथ क्षतिपूर्ति सम्बन्धी विचार-विमर्श तथा अदालत में प्रस्तुत करने के लिए भी प्रयोग में लाया जा सकता है।

इस नवीन तकनीक पर विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करें:

एचएलआरएन, फोन: 011-24358492 पदवीपब.ंतचण्वतह

बेदखली असर आकलन, बलजीत नगर, दिल्ली

एचएलआरएन ने अन्य सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर बलजीत नगर दिल्ली (एक ऐसी बस्ती जो दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मार्च 2011 में हस्त कर दी गयी थी) में दो बार 'बेदखली असर आकलन का कार्यक्रम आयोजित किया। तथ्यों पर आधारित पहला अध्ययन कार्यक्रम बेदखली (जून 2011) के तीन माह बाद आयोजित किया गया जिसमें हस्तिकरण से हुए सीधे नुकसान के लिए प्रति घर के हिसाब से 60,000-70,000 रुपये के औसत नुकसान का निर्धारण किया गया। ये तथ्य दिल्ली उच्च न्यायालय में भी प्रस्तुत किये गये। दूसरा अध्ययन कार्यक्रम बेदखली के एक वर्ष बाद (जुलाई 2012) में आयोजित किया गया जिसमें प्रति घर के हिसाब से औसत नुकसान का निर्धारण विश्लेषण अभी प्रतीक्षारत है।

5. तथ्य खोज अभियान (फैक्ट फाइंडिंग)

तथ्य खोज अभियान के लिए किसी संस्था संगठन की सहायता लें जो जबरन बेदखली से संबंधित सही तथ्य, साक्ष्य एवं प्रमाण जुटाने में उपयोगी हो सके। इस मिशन का उद्देश्य अधिकारों के उल्लंघन सम्बन्धी दस्तावेज तैयार करना तथा न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में संस्तुतियां तैयार करना है। इस तथ्य खोज अभियान की रिपोर्ट कानूनी बहस के उद्देश्यों के लिए भी उपयोग में लायी जा सकती है। आप किसी खास बेदखली की घटना पर सूचनाएं एकत्रित करने के लिए तथा नागरिक अधिकारों की जागरूकता के लिए सार्वजनिक सुनवाईयां और जन अदालतों का आयोजन भी कर सकते हैं।

6. सांसदों विधायकों पर दबाव डालना

व्यापक पैमाने में ध्वस्तीकरण पर हस्तक्षेप के लिए घर छिन जाने के मुद्दों को लेकर सांसदों और विधायकों से मिलकर अपने पक्ष में जनमत खड़ा करें।

7. सविनय अवज्ञा कार्यक्रम आयोजित करना

-जन सुनवाई

जिन लोगों के मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है उन्हें कोई तिथि, समय और स्थान निश्चित कर जन सुनवाई का आयोजन करना चाहिए। जन सुनवाई में मानवाधिकारों से संबंधित विषय के जानकार लोगों का एक पैनाल बनाया जाना चाहिए जो पीडित लोगों की समस्याओं को सुनकर एक निष्कर्ष या राय पर पहुंचेंगे। उस राय को सरकार और संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाया जाना चाहिए। जन सुनवाई का कापफी महत्व होता है और उससे सरकार और उसके नुमाइंदों पर सही पहल के लिए एक दबाव बनता है। वहीं दूसरी तरफ पीडित जनता के पक्ष में माहौल खड़ा होता है।

- धरना रैली

समुदाय तथा सहयोगियों को साथ लेकर जिम्मेदार सरकारी अधिकारियों के कार्यालय के बाहर धरना-प्रदर्शन करें। घटनास्थल पर मीडिया को बुलाएं और एक मांगपत्र तैयार करें तथा उसके साथ कानूनों व मानवाधिकारों के उल्लंघन की सूची बनाकर सक्षम सरकारी अधिकारियों को प्रस्तुत करें।

-चक्का जाम

किसी नियत तिथि पर सभी व्यावसायिक वाहनों को किसी विशेष सड़क अथवा सड़क के पर संचालन न करने की अपील करें अथवा बेदखली व मानवाधिकारों के उल्लंघन पर लोगों को जागरूक करने के लिए तथा अपनी मांगों के समर्थन में किसी स्थान विशेष पर चक्का जाम कर सरकार पर दबाव बनायें।

- काला दिवस

सरकारी कार्यवाही पर रोष व्यक्त करने, विरोध दर्ज करने के लिए काले झंडे लहराकर, काली पट्टी, कपड़े और बैज लगाकर काला दिवस मनायें।

8. पत्र लेखन पोस्ट कार्ड अभियान

- पत्र लेखन अभियान शुरू करने के लिए आनलाइन पत्र तैयार करें और उसमें अपने मुद्दों का विवरण लिखकर बड़े पैमाने पर ईमेल सूची द्वारा लोगों को भेजें तथा उनसे अन्य लोगों को प्रोत्साहित व जागरूक करने हेतु भेजने के लिए अनुरोध करें। आप अधिक से अधिक लोगों का हस्ताक्षर युक्त पत्र भी लिख सकते हैं इसके लिए विधायकों, कालेजों, संस्थानों तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों में संपर्क किया जा सकता है।

- उचित प्राधिकरण को अपनी चिंताओं से अवगत कराने के लिए पोस्ट कार्ड भेजें।

इस तरह का एक अभियान पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र के शाहबाद डेयरी स्थित सरकारी और दिल्ली नगर निगम के स्कूली बच्चों द्वारा चलाया गया जिसमें लगभग 180 प्रतिभागियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश को पोस्ट कार्ड भेजकर स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं तथा शिक्षा की गुणवत्ता में कमियों को व्यक्त

किया।

चेन्नई में पत्र लेखन अभियान

वर्ष 2009 में चेन्नई की एक मलिन बस्ती में रहने वाले लगभग 300 बच्चों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री एम के करुणानिधि को 'प्रिय दादाजी संबोधित कर एक पत्र भेजा। बच्चों ने उनसे शिक्षा सत्र के बीच में उनके घरों को न ढहाये जाने के लिए प्रार्थना की। इस कार्य के परिणामस्वरूप चेटपेट स्थित अप्पास्वामी गली के मलिन बस्ती निवासियों को उच्च न्यायालय चेन्नई से बेदखली पर रोक लगाने का स्थगन आदेश मिल गया।